

भारत-जापान के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक मंत्रिस्तरीय बातचीत के बारे में संयुक्त प्रेस वक्तव्य

रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के निमंत्रण पर जापान के रक्षा मंत्री श्री इत्सुनोरी ओनोदेरा 19 से 20 अगस्त, 2018 तक भारत की यात्रा पर हैं। दोनों मंत्रियों के बीच 20 अगस्त, 2018 को नई दिल्ली में वार्षिक बैठक हुई। ओनोदेरा ने आज प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की। दोनों मंत्रियों ने इस बात पर गौर किया कि जापान और भारत के प्रधानमंत्रियों ने सितंबर, 2017 में दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग बढ़ाने के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के महत्व पर बल दिया था। दोनों नेताओं ने रचनात्मक तरीके से विचारों का आदान-प्रदान किया। दोनों मंत्रियों ने

इस बात को साझा किया कि 'जापान-भारत विशेष रणनीतिक और ग्लोबल साझेदारी के अंतर्गत' दोनों देशों के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग को मजबूत बनाना अत्यावश्यक है जो मिलकर कार्य करने के लिए 'जापान की मुक्त और खुली भारत-प्रशांत रणनीति' को भारत की 'एकट ईस्ट नीति' से साझा उद्देश्यों को हासिल से जोड़ता है।

दोनों मंत्रियों का मानना था कि भारत-प्रशांत क्षेत्र में शांति और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में शांति और स्थिरता आवश्यक हैं। दोनों नेताओं ने कोरिया प्रायद्वीप के घटनाक्रम सहित

क्षेत्र में वर्तमान सुरक्षा स्थिति के बारे में विचारों का आदान-प्रदान किया। दोनों नेताओं ने जापान के चीफ ऑफ स्टॉफ, ज्वाइंट स्टॉफ के बातचीत में भाग लेने का स्वागत किया जो जापान के रक्षा मंत्रालय की ओर से बातचीत में पहली भागीदारी थी। दोनों नेताओं ने समुद्र में सुरक्षा की दिशा में सहयोग बढ़ाने में दिलचस्पी दिखाई और जापान नौबहन आत्म-रक्षा बल (जेएमएसडीए) और भारतीय नौसेना के बीच गहरे सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर करने की दिशा में मिलकर कार्य करने का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के रक्षा प्रतिष्ठानों के बीच हर स्तर पर

नियमित बातचीत करने, अधिक टोस और प्रभावी आधार बनाने, नौबहन और वायु सहयोग बढ़ाने की इच्छा व्यक्त की। दोनों नेताओं का मानना था कि संस्थागत बातचीत और एक दूसरे के देशों की यात्राएं, जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स (जेजेएसडीएफ) और भारतीय सेना के बीच आदान-प्रदान, जापान नौबहन आत्म-रक्षा बल और भारतीय वायु सेना के बीच आदान-प्रदान, शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में आदान-प्रदान, रक्षा उपकरण प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाया जा सकता है।

कॉस्मो फिल्मस ने उन्नत किस्म की सिंथेटिक कागज लांच की

अहमदाबाद, बीओपीपी फिल्मों की प्रमुख निर्माता कंपनी कॉस्मो फिल्मस लिमिटेड ने सिंथेटिक पेपर की एक उन्नत संस्करण लांच की है। जो कई दैनिक अनुप्रयोगों में कागज की जगह ले सकता है। यह कागज वास्तव में बीओपीपी फिल्मस आधारित है, जो दिखने और इस्तेमाल करने में कागज की तरह है। हालांकि सिंथेटिक कागज एक प्लास्टिक आधारित उत्पाद है, जो पानी, तेल, रसायन और दाग प्रतिरोध होता है। कंपनी को इस पहल से कागज उद्योग में एक बड़ा बदलाव आ सकता है। कागज उद्योग में आएगा बड़ा बदलाव

रोजमर्रा के जीवन में ऐसे असंख्य अनुप्रयोग हैं, जिसमें कागज के स्थायित्व, संरक्षण और पुनः उपयोग की आवश्यकता होती है, वर्तमान में

भारत सरकार भी करेसी नोट में सिंथेटिक पेपर के इस्तेमाल के लिए एक प्रायोगिक परियोजना पर काम कर रही है। चीन में इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है, अब भारत में भी सिंथेटिक कागज उद्योग के विकसित होने की असीम संभावनाएं हैं, कागज का यह प्लास्टिक संस्करण आज के परिदृश्य में भी प्रासंगिक है। जहां पर्यावरण संरक्षण एवं संवहनीयता के उपयोगों की जरूरत है, सिंथेटिक कागज को न केवल दोबारा इस्तेमाल में लाया जा सकता है, बल्कि इसकी विनिर्माण प्रक्रिया भी काफी हद तक पर्यावरण के अनुकूल है क्योंकि इसके लिए पेड़ों को काटना जरूरी नहीं होता है और इसे बड़े पैमाने पर उपलब्ध चुना पत्थर से बनाया जाता है, यह जल संरक्षण और प्रदूषण को कम करने में मदद करता है। (3-1)

सेम्बकार्प एनर्जी ने जीता 250 मेगावाट बिजली सप्लाई करने का टेंडर



गुरुग्राम, सेम्बकार्प एनर्जी इंडिया लिमिटेड (एसईआईएल - SEIL) ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी सेम्बकार्प गायत्री पावर लिमिटेड (एसजीपीएल - SGPL) के जरिए, बांग्लादेश को कुल 15 साल के लिए 250 मेगावाट बिजली आपूर्ति करने का कॉम्पिटिटिव टेंडर जीता है। ये टेंडर बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड (बीपीडीबी - BPDB) ने लॉन्च किया था और इसके जरिए बांग्लादेश के बिजली आपूर्ति हेतु बोली लगाने के लिए भारतीय बिजली कंपनियों को आमंत्रित किया गया था।

एसजीपीएल (SGPL) को अल्प और दीर्घकालिक अवधियों के लिए लगाई गई बोलियों में जीत की सूचना बीपीडीबी (BPDB) ने आधिकारिक रूप से लेटर ऑफरिडेंट (एलओआई - LOI) जारी करके दे दी है। इसके

मुताबिक आधिकारिक प्रक्रियाओं और सभी संबंधित सरकारी मंजूरीयों के बाद बांग्लादेश को बिजली आपूर्ति शुरू की जाएगी। विपुल टुली, मैनेजिंग डाइरेक्टर (प्रबंध निदेशक), एसईआईएल (SEIL) ने कहा: "हमें इस टेंडर के सफल होने की खुशी है और हम एक ऐसे दर पर बिजली आपूर्ति करने जा रहे हैं जो न केवल बांग्लादेश के लिए आकर्षक है बल्कि एसईआईएल के लिए भी सस्टेनेबल है। साथ-ही-साथ, ये भारत-बांग्लादेश के बीच लगातार बढ़ रहे आर्थिक रिश्तों के अनुरूप भी है। प्रतिस्पर्धात्मक लागत, विश्वसनीय बिजली आपूर्ति और अपनी बची हुई क्षमता को व्यावहारिक दरों पर अनुबंधित करने को एसईआईएल की स्ट्रेटिजिक नीतियों के मुताबिक ही हमने ये बोली लगायी थी।" (1)

हाई सिक्वोरिटी नंबर प्लेट 31 अगस्त तक लगवाना अनिवार्य



अहमदाबाद: केन्द्रीय मोटर वाहन नियम में किये गये प्रावधान अनुसार वाहनों पर हाई सिक्वोरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) लगाने का कार्य आरटीओ में युद्धस्तर पर चल रहा है। तमाम पुराने वाहन में एचएसआरपी लगाना अनिवार्य है, 16 नवम्बर, 2012 से इसे लागू किया गया है। पुराने वाहन में एचएसआरपी लगाने

की अंतिम तारीख 31.07.2018 घोषित की गयी थी लेकिन अनेक नागरिक अंतिम तारीख तक में भी ऐसी नंबर प्लेट लगाना नहीं सके। नागरिकों की कठिनाई को देखते हुए सरकार ने हाई सिक्वोरिटी नंबर प्लेट लगाने की तारीख 31.08.2018 तक के लिए बढ़ा दी थी।

वाहन परिवहन कार्यालय के विशेष कार्यरत अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि इस समयवाधि तक तमाम वाहन चालक को अनिवार्य था, वैसे देखकर थोड़ा शांत महसूस करेंगे। नारंगी और सुनहरे कढ़ाई वाले लहंगे और नारंगी



केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, जहाजरानी और जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्री श्री नितिन गडकरी नई दिल्ली में नदियों के अन्तर्गोचन हेतु विशेष समिति की पंद्रहवीं बैठक और राष्ट्रीय जल विकास अधिकरण सोसाइटी की बत्तीसवीं वार्षिक सामान्य बैठक की अध्यक्षता करते हुए। केन्द्रीय संसदीय मामलों, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण राज्यमंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल और जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय के सचिव श्री यू.पी.सिंह भी उपस्थित थे।

राज्यसभा के सभापति, लोकसभा अध्यक्ष ने सांसदों से केरल बाढ़ राहत के लिए उदारतापूर्वक दान देने की अपील की

उपराष्ट्रपति तथा राज्यसभा के सभापति श्री एम. वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन ने आज संसद सदस्यों (राज्यसभा तथा लोकसभा) से अपनी-अपनी एमपीलैड निधियों से केरल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए उदारतापूर्वक दान देने का आग्रह किया और सांसदों से कहा कि इसके लिए वे एक महीने का अपना वेतन दें। संसद के दोनों पीठासीन अधिकारियों ने केरल में राहत कार्य के लिए एक महीने का अपना वेतन देने के निर्णय की घोषणा की।

उपराष्ट्रपति के सरकारी निवास पर श्री नायडू और श्रीमती महाजन की मुलाकात हुई तथा दोनों पीठासीन अधिकारियों ने संयुक्त अपील जारी करने से पहले केरल में नुकसान के बारे में विचार विमर्श किया। श्री नायडू द्वारा सांसदों से की गई अपील मीडिया

के समक्ष जारी करते हुए कहा गया है- 'माननीय सदस्य अवगत हैं कि बाढ़ के कारण केरल के विभिन्न हिस्सों में बड़े पैमाने पर बर्बादी हुई है और लोगों की मृत्यु हुई है। संपत्ति को नुकसान के अतिरिक्त हजारों लोग फंसे पड़े हैं। केरल में बाढ़ की भयावहता की स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने इसे 'गंभीर प्रकृति' की आपदा घोषित किया है। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के दिशा-निर्देशों के पैराग्राफ 2.8 में कहा गया है, - 'देश के किसी भाग में गंभीर आपदा की स्थिति में संसद सदस्य प्रभावित जिले के लिए अधिकतम एक करोड़ रुपये तक के कार्यों की सिफारिश कर सकते हैं।'

हम संसद के सभी सदस्यों से एमपीलैड निधि से केरल के प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए धन देने की अपील करते हैं। यह

एमपीलैड दिशा-निर्देशों के अंतर्गत अनुमति योग्य है। हम दोनों ने इस नेक और मानवीय कार्य के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में अपना एक महीने का वेतन देने का निर्णय लिया है। हम संसद के सभी सदस्यों से एक महीने का वेतन देने पर विचार करने की अपील करते हैं। श्री नायडू तथा श्रीमती सुमित्रा महाजन उदार सहायता देने के लिए राज्यसभा तथा लोकसभा के सदस्यों को पत्र लिखेंगे, जिसमें आज की गई संयुक्त अपील को संलग्न किया जाएगा। श्री नायडू के निर्देश पर राज्यसभा सचिवालय ने इस महीने की 16 तारीख को केरल में आपदा के आकार के सरकारी मूल्यांकन के बारे में गृह मंत्रालय को पत्र लिखा और सरकार ने स्पष्ट किया कि केरल में बाढ़/भूस्खलन की भयावहता स्थिति को देखते हुए सभी व्यावहारिक उद्देश्य के लिए यह आपदा

'गंभीर प्रकृति' की आपदा है। श्री नायडू ने आज राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश, वरिष्ठ अधिकारियों से भी बातचीत की। श्री हरिवंश एमपीलैड समिति के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने नुकसान की गंभीरता के बारे में राज्यसभा के पूर्व उपसभापति प्रो. पी.जे. कुरियन से भी बातचीत की। प्रो. कुरियन केरल में हैं। एमपीलैड दिशा-निर्देशों के अनुसार सरकार यदि किसी आपदा की 'गंभीर प्रकृति' की आपदा घोषित करती है, तो संसद सदस्य राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए एक करोड़ रुपये का योगदान कर सकते हैं। दिशा-निर्देशों में यह भी कहा गया है कि जिस दिन से संसद सदस्य ऐसा योगदान करेंगे, उसी दिन से संबंधित अधिकारी को एक महीने के अंदर राहत कार्यों को चिन्हित करना होगा और इस पर आठ महीने के अंदर अमल करना होगा।

केरल में राहत एवं बचाव कार्य जारी, खाद्यान्न और आवश्यक दवाएं भेजना जारी

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति (एनसीएमसी) की आज यहाँ पांच दिन में पांचवीं बार बैठक हुई जिसमें केरल के बाढ़ प्रभावित इलाकों में चल रहे राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की गई। मंत्रिमंडल सचिव श्री पी.के.सिन्हा ने बैठक में अध्यक्षता की। केरल के मुख्य सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल हुए। उन्होंने बताया कि वर्षा कम हुई है और बाढ़ का पानी घटना शुरू हो गया है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने आज 100 मीट्रिक टन दालें भेजीं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आपात स्थिति में काम आने

वाली 52 मीट्रिक टन दवाएं भेजीं। अन्य 20 मीट्रिक टन दवाएं आज रात तक केरल पहुंच जाएंगी। 20 मीट्रिक टन ब्लिचिंग पाउडर और एक करोड़ क्लोरीन की टैबलेट भी कल भेजी जाएंगी। 12 चिकित्सा कर्मियों की टीम को तैयार रखा गया है। अब तक कहीं से कोई बीमारी फैलने की खबर नहीं मिली है। दूरसंचार विभाग ने 77,000 टावरों (रफ्त में कुल 85,000 टावरों में से) को काम करने लायक बना दिया है। 1407 टेलीफोन एक्सचेंजों में से 13 को छोड़कर सभी काम करने लगे हैं।

दूरसंचार विभाग ने लापता व्यक्तियों का पता लगाने में मदद के लिए हेल्लपलाहन नंबर 1948 दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 12,000 किलोलीटर कैरोसिन उपलब्ध कराया है। एलपीजी सिलेंडरों का वितरण करने के लिए भी पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। विमानों के लिए भी पर्याप्त इंधन उपलब्ध कराया गया है।

मवेशियों के लिए 450 मीट्रिक टन चारा भेजा गया है। पशु चिकित्सा से जुड़ी दवाओं को दो खेप भेजी जा चुकी

है। रेलवे ने पानी और राहत सामग्री की निःशुल्क आपूर्ति करने की पेशकश की है। पशु पाकन और डेरी विभाग ने दूध और दूध के पाउडर की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराई है। एनसीएमसी की बैठक में स्वास्थ्य, दूरसंचार, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, बिजली, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के सचिव तथा रक्षा बलों, गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

गडकरी ने नदियों को आपस में जोड़ने पर संबंधित राज्यों के बीच सहमति विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया

केन्द्रीय जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा संरक्षण, शिपिंग, सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने आज नदियों को आपस में जोड़ने पर संबंधित राज्यों के बीच सहमति विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि समुद्र में गिरने वाले पानी का उपयोग आवश्यकता वाले इलाकों में किया जा सके। उन्होंने राज्यों से कहा कि राज्य संबंधी विषयों पर सक्रिय विचार-विमर्श से समाधान निकाले, ताकि प्राथमिकता के आधार पर परियोजनाएं लागू की जा सकें। देश की जल और खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के लिए नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना को शीघ्र लागू करने के लिए कदम उठाए गए हैं और इन परियोजनाओं को लागू करने के लिए सहमति ज्ञापन को संबंधित राज्य सरकारों से विचार विमर्श करके अंतिम रूप दिया जा रहा है। पांच परियोजनाओं में - केन-बेतवा संपर्क परियोजना, दमन-गंगा-पिंपाल संपर्क परियोजना, पार-तापी-नर्मदा संपर्क परियोजना, गोदावरी-कावेरी (ग्रेंड एनिकट) परियोजना तथा पार्वती-

काली-सिंधु-चंबल परियोजना शामिल हैं। राज्य के बाहर से नदियों को जोड़ने के लिए राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी से नौ राज्यों झुं महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड, ओडिशा, बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक तथा छत्तीसगढ़ - से 47 प्रस्ताव प्राप्त किए हैं। इन परियोजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करने से बाढ़ के समय आपदा में कमी आएगी, सिंचाई सुविधाओं में सुधार होगा, ग्रामीण कृषि में रोजगार-विमर्श से समाधान होगा तथा नियात बढ़ेगा और गांव से बाहर जाने वाले लोगों की संख्या में कमी आएगी। श्री गडकरी ने यह सुझाव भी दिया कि नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजनाओं की बाधाओं को दूर करने के लिए अंतर-राज्य तथा केन्द्र-राज्य विषयों को हल करने की उचित कानूनी व्यवस्था बनाने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजनाओं में यह व्यवस्था अतिम रूप दिया जा रहा है। पांच परियोजनाओं में - केन-बेतवा संपर्क परियोजना, दमन-गंगा-पिंपाल संपर्क परियोजना, पार-तापी-नर्मदा संपर्क परियोजना, गोदावरी-कावेरी (ग्रेंड एनिकट) परियोजना तथा पार्वती-



हर किसी के लिए अपने बालों की देखभाल करना एक आवश्यक दिनचर्या है, लेकिन यह और भी महत्वपूर्ण है कि इसे सही तरीके से पोषित किया जाए। अक्सर, लोग मानते हैं कि नियमित रूप से शैम्पू करना ही पर्याप्त है। लेकिन हर वॉश से पहले अपने बालों को तैयार करना और 'शैम्पू की तैयारी' करना आवश्यक है।

जरूरत से अधिक शैम्पू बालों से आवश्यक नमी को बाहर कर देता है और इसलिए पैराशूट एडवांस्ड कोकोनट हेयर ऑयल के साथ कुछ आवश्यक 'शैम्पू की तैयारी' में शामिल होना महत्वपूर्ण है। पैराशूट एडवांस 10 परतों तक अंदर जाता है और बालों को गहरा

पोषण प्रदान करता है और उन्हें खराब होने से बचाता है। पैराशूट एडवांस्ड ने अभिनेत्री कृति सेनन और उनकी बहन नूपुर सेनन को अपना ब्रांड एंबेसडर बनाया है और उन्हें इस ऑयल के साथ अपना 'गहरा लव' व्यक्त करने का मौका दिया है। सेट्स पर दोनों बहनों को इस संबंधी अपने कई सारे किस्से शेयर करते हुए देखा काफ़ी रोमांचक लगता है और कृति भी नूपुर की बड़ी बहन होने का दायित्व अच्छी तरह से समझती है। अपने इस प्यार को व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि वे इसकी मदद से अपने बालों की देखभाल काफ़ी अच्छे से कर पाती हैं। (1-7)